राजस्थान बजट 2020—21

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण का आरंभ देश की गिरती अर्थव्यस्था और व्याप्त मंदी से किया और राज्य की अर्थव्यस्था के केन्द्र की नीतियों से प्रभावित होने को रेखांकित किया। ऐसे में जब देश और राज्य आर्थिक मंदी से जुझ रहा है, आवश्यकता ऐसे उपाय करने की है जिससे बाज़ार में मांग बढ़े और लोगों को काम मिले। इस बजट में इस दृष्टि मुख्यमंत्री ने राज्य में खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी रखने की बात कही है और कहा है कि आगामी वर्ष में 53 हजार नई भर्तीयां की जाएंगी साथ ही बजट से कौशल एवं तकनीक पर ज़ोर दिया गया है। औद्योगिक विकास नीति 2019 और निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के अलावा, इस बजट में 'बोर्ड ऑफ इन्वेस्मेंट' के गठ़न की घोषणा की गई है, जिससे यह उम्मीद की गई है कि राज्य में निवेश बढ़ेगा। साथ ही राजस्थान अनु.जाति एवं जनजाति वित्त विकास निगम के माध्यम से 50 हजार युवाओं को ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है जिससे वे स्वरोजगार कर सकें। बजट में भवन निर्माण क्षेत्र को कई छुट और लाभ दिये गये हैं जिससे इस क्षेत्र को मंदी से उबारा जा सकें। लेकिन ग्रामीण विकास जिसके अंतर्गत ग्रामीण रोजगार के कार्यक्रम भी आते हैं, के बजट में कटौती की गई है।

बजट में किसानों के लिये भी घोषणाएं हुई हैं। वर्षा जल संग्रहण के लिये 12,500 फॉर्म पौण्ड, सुक्ष्म सिंचाई प्रणाली (ड्रिप एवं स्प्रींकलर) सौर उर्जा पंप, 2 लाख टन युरिया और 1 लाख टन डीएपी का भंडारण के साथ 44 नई स्वतंत्र कृषि मण्डियां और 100 गौण मंडियां प्रस्तावित हैं। सबसे महत्त्वपूण यह है कि पुर्वी राजस्थान नहर परियोजना को उच्च प्राथमिकता दिये जाने की घोषणा हुई है जिससे 13 जिलों में सिंचाई की सुविधा होने का दावा किया गया है।

सामाजिक क्षेत्रों में 'निरोगी राजस्थान' के माध्यम में से सबसे ज्यादा स्वास्थ्य की चर्चा हुई। हालांकि स्वास्थ्य का बजट विशेष नहीं बढ़ा। लेकिन 100 करोड़ रूपए के निरोगी 'राजस्थान प्रबंधन कोष'

और खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने क सख्त उपाय जैसे हर जिले में जांच की प्रयोगशाला, राज्य में कैंसर रजिस्ट्री प्रारंभ करने और 150 चिकित्सा संस्थनों में दंत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने की घोषणा हुई है। वहीं शिक्षा के लिये कुल बजट में भी कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन राज्य में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों को शेष सभी ब्लॉक में खोला जायेगा, कम्प्युटर शिक्षक कैडर बनाया जायेगा और इस वर्ष 22 नये कस्तुरबा गांधी विद्यालय खोले जायेंगे, ऐसी घोषणा हुई है।

जहां तक अन्य सामाजिक सेवाओं की बात है, उनके बजट में भी कोई वृद्धि नहीं हुई है। अनु.जाति, जनजाति एवं पिछले वर्गों का कल्याण (अल्पसंख्यक सहित), सामाजिक कल्याण एवं पोषण, ग्रामीण विकास, विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण का बजट कम हुआ है, वहीं श्रम कल्याण, जिसके अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता आता है, और शहरी विकास तथा पेयजल एवं स्वच्छता का बजट मामुली बढ़ा है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में, पुंजीगत बजट में बढ़ोत्तरी की गई है जो अच्छा संकेत है। लेकिन, विशेषकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगभग आधे पूंजीगत बजट का उपयोग (खर्च) नहीं हो पाता है जिसके कारण स्वास्थ्य केन्द्रों में भौतिक सुविधाओं, चिकित्सा मशीनों की कमी बनी रहती है। आशा है सरकार इन क्षेत्रों में पूंजीगत खर्च की पूर्ण उपयोगिता सुनिश्चित करेगी।

आर्थिक क्षेत्रों में कृषि एवं संबद्ध सेवाओं का बजट बढ़ा है। इसमें भी मुख्यतः सहकारिता, जिसके अंतर्गत ऋण माफी योजना आती है, का बजट बढ़ा है। साथ ही सिंचाई मद के बजट में एक हजार करोड़ रूपए की बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन उर्जा क्षेत्र के बजट में लगभग 10 हजार करोड़ रूपए की भारी कटौती हुई है।

बजट में आने वाले वर्ष में कई नई नीतियां लाने की भी घोषणा हुई है। जैसे– किसान उत्पादक संगठन नीति, महिला कल्याण नीति, हस्तशिल्प नीति और स्टार्ट अप नीति, राज्य सरकार को राज्य में कृषि नीति के मसौदा को अन्तिम रूप देने और महिला कल्याण की जगह महिला सशक्तिकरण नीति लाने पर विचार करना चाहिये।

जैसी आशंका थी आर्थिक मंदी का असर भी इस बजट पर साफ दिखा है। चालु वर्ष की राजस्व प्राप्तियों में 8 हजार करोड़ रूपए की कमी का अनुमान है, जो मुख्यतः 'केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्सें' में कमी के कारण हुआ है। हालांकि केन्द्रीय सहायता मद में राज्य को अनुमानित बजट से 4 हजार करोड़ रूपए अधिक प्राप्त होने का संशोधित अनुमान है। राज्य सरकार के स्व–कर में भी 3 हजार करोड़ की कमी की अनुमान है। वहीं राज्य सरकार का गैर–कर राजस्व जरूर 19 हजार करोड़ रूपए से बढ़कर 19.5 हजार करोड़ रूपए हो जाने का अनुमान है। ऐसे में आगामी वर्ष के बजट में राजस्व के अनुमान भी प्रभावित होते हैं। फिर भी राज्य सरकार ने आने वाले वित्तीय वर्ष (2020–21) में कुल 1.73 लाख करोड़ रूपए के राजस्व आय का अनुमान रखा है, जो चालु वित्तीय (2019–20) वर्ष के बजट अनुमान से 9 हजार करोड़ रूपए अधिक है। जबकि राजस्व खर्च 1.85 लाख करोड़ रूपए रखा गया है जो चालु वर्ष में 1.77 लाख करोड़ रूपए होना अनुमानित था।

राज्य सरकार ने घाटे का बजट पेश किया है। वर्ष 2020–21 में सरकार का राजस्व घाटा (राजस्व आय – राजस्व व्यय) 12.3 हजार करोड़ होना अनुमानित है। जबकि राजकोषिय घाटा 33.92 हजार करोड़ रहने को अनुमान है जो राज्य के सकल घरेलु उत्पाद का 2.99 प्रतिशत रहेगा। यहां यह ध्यान रखना होगा कि राजकोषिय उत्तरादायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार राजस्व घाटा शुन्य होना चाहिए।

जहां तक इस बजट के अनुमानों का वास्तविकता में खरा उतरने का सवाल है तो वह इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले वर्ष में देश व राज्य की आर्थिक स्थिति किस ओर जाती है और राज्य सरकार द्वारा अनुमानित राजस्व आय का कितना प्रतिशत वास्तव में उपलब्ध हो पाता है। अगर सरकार के राजस्व अनुमान और वास्तविक आय में अंतर होता है तो सरकार के लिये राजकोषिय घाटे को भी राज्य के सकल घरेलु उत्पाद के 3 प्रतिशत के अन्दर रखना भी मुश्किल हो सकता है।